सुविचार
खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।
-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-273 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शनिवार 07 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

राजस्थान सरकार की तीर्थ योजना पर अमल, पहली ष्ट ट्रेन से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान, सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

जयपुर। देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना- 2025 के अन्तर्गत बजट घोषणा अनुसार पहली वातानुकूलित ट्रेन शुक्रवार को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई। इस राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने रिबन काटकर तीर्थ यात्रियों को कोच में प्रवेश दिलाया। रेलवे स्टेशन, जयपुर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, जिलाध्यक्ष अमित गोयल, महापौर सौम्या गुर्जर, देवस्थान विभाग के शासन सचिव केके पाठक, आयुक्त वासुदेव मालावत, डीआरएम विकास पुरवार, अतिरिक्त आयुक्त प्रथम रतनलाल योगी, द्वितीय महेंद्र देवतवाल आदि मौजूद रहे।

इससे पहले आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन में साउंड सिस्टम लगाकर धार्मिक भजन सुनाने के लिए कहा। इससे धनुषकोटि, ब्रह्मकुंड और मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन मुख्य रूप से कराएगी। देवस्थान विभाग की तीर्थयात्राओं में यह

पहले जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान किया।

देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सवाईमाधोपुर के रास्ते रामेश्वरम, मदुरै की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला व पटवस्त्र भेंट किए गए हैं। आठ दिवसीय यात्रा में यह ट्रेन रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, सर्वाधिक दूरी की यात्रा है। यात्रा में सभी यात्रियों की देख-रेख हेतु एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में दो सरकारी कर्मचारी अनुदेशक, साथ ही एक डॉक्टर व दो नर्सिंग अधिकारी भी रहेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए देवस्थान विभाग की ओर से भोजन, भ्रमण, यातायात व रुकने की व्यवस्था निश्शुल्क रहेगी।

उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया गया है कि राजस्थानी वरिष्ठजन इस ट्रेन में सवार होकर अपनी धरती व संस्कृति पर गर्व कर सकें, साथ ही यह ट्रेन जहां जाये, वहां अन्य लोगों को भी आकर्षित कर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दे। राजस्थान की प्रकृति व संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित यह ट्रेन बाहर से पैलेस ऑन व्हील्स से भी अधिक भव्य दिखेगी। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में कुल 14 कोच हैं, जिसमें 10 यात्री कोच हैं। राजस्थान के दुर्ग, पुरासम्पदा, मंदिर, नृत्य, वाद्य, उत्सव, कला आदि वैशिष्ट्य की थीम पर अलग-अलग डिब्बों को सजाया गया है। मरुधरा में सूर्योदय व सूर्यास्त की स्वर्णिम आभा को प्रदर्शित करने के लिए इसकी थीम में पीताभ केसरिया रंग को वरीयता दी गयी है। डिजाइन में राजस्थान के राजसी स्वरूप के साथ-साथ मंदिर व शुभत्व के विविध प्रतीकों व चिह्नों का भी प्रयोग किया गया है। डिजाइन में राजस्थान की पहचान बने पशु-पक्षियों को भी विशेष स्थान दिया गया है। इनमें गाय व ऊँट के अतिरिक्त रणथम्भौर के बाघ व तालछापर के कृष्णमृग को भी स्थान दिया गया है।

ट्रेन में एक कोच को विशेष रूप से भारतीय सेना में राजस्थान के योगदान को समर्पित किया गया है, जिसमें जैसलमेर वार म्यूजियम, तनोट बॉर्डर, महाजन (महाद्वीप की सबसे बड़ी) फायरिंग रेंज का चित्रण प्रमुख है। पैंट्री कार में राजस्थान के व्यंजनों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। केर-साँगरी, बाजरे की रोटी, राबड़ी, लस्सी, कुल्फी आदि का प्रदर्शन किया गया है। इसी प्रकार पावर कार को भी विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या के रामलला की सजीव झांकी सजाई गई। इसके साथ ही कांवड़ और उसमें बैठे वरिष्ठजनों का प्रतीकात्मक मॉडल भी रखा गया।

बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं फैला रही-सचिन

टोंक। सचिन पायलट ने कहा कि जिस दिन सीजफायर की घोषणा हुई, उसी दिन कुछ घंटों के भीतर सीमा पार से गोलीबारी और बमबारी शुरू हो गई। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश के सीजफायर आश्वासन पर विश्वास करना समझदारी नहीं है।

टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन टोंक विधायक और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जनता से सीधा संवाद करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, विकास के नाम पर जमीनी हकीकत शून्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जो काम शुरू हुए थे, उनकी देखरेख तक यह सरकार नहीं कर रही है। अफसरों की मनमानी और सत्ताधारी नेताओं की लाचारी से प्रदेश की जनता त्रस्त है।

जनसुनवाई में उठीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश

पायलट ने दौरे की शुरुआत सर्किट हाउस में जनसुनवाई से की, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा

कि जनता की सुनवाई और समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि सत्ता बचाने की जद्दोजहद।

ऑपरेशन सिंदूर% पर उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' और सीजफायर को लेकर जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस दिन सीजफायर की घोषणा हुई, उसी दिन कुछ घंटों के भीतर सीमा पार से गोलीबारी और बमबारी शुरू हो गई। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश के सीजफायर आश्वासन पर विश्वास करना समझदारी नहीं है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उनके किसी भी वादे पर यकीन करना सबसे बड़ी भूल होगी।

'भारत की तुलना पाकिस्तान से करना हास्यास्पद'

सचिन पायलट ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है। इसके बावजूद भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से गलत है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत को सावधानी के साथ रणनीति बनानी चाहिए, न कि भावनात्मक नारों और घोषणाओं के सहारे।

'सरकार दिल्ली के आकाओं को खुश करने में व्यस्त'

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि पूरी सरकार सत्ता के संघर्ष और कुर्सी बचाने में लगी हुई है। अफसरों का दबदबा है और योजनाएं कागजों में सिमट गई हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता का दुख-दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सत्ता में बैठे बड़े-बड़े नेता भी आज रोते फिर रहे हैं।

राजस्थान में कोविड-19 के मामले बढ़े, 15 नए मरीज, जयपुर में 101 केस

जयपुर। राजस्थान में कोविड-19 एक बार फिर पैर पसार रहा है. शुक्रवार को प्रदेश में 15 नए कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए. इस साल अब तक कुल 183 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है. जयपुर सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कुल 101 मामले दर्ज किए गए हैं. उदयपुर में 21 और जोधपुर में 15 मामले सामने आए हैं. अन्य जिलों में भी छिटपुट मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें डीडवाना, अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, फलोदी और बालोतरा शामिल हैं.

स्वास्थ्य विभाग का बयान

जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मौसमी बदलाव के कारण वायरल

गतिविधियों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. उन्होंने कहा, वर्तमान में 20-25 मामले सामने आ रहे हैं, जो मौसमी बदलाव से जुड़े हैं. स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अनुसार नए वैरिएंट्स की मौजूदगी पुष्टि हुई है, लेकिन ये गंभीर नहीं हैं. एसएमएस कॉलेज ने बुजुर्गों, बच्चों, और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भीड़ में मास्क पहनने की सलाह दी.

बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (ह्वढ्ढङ्क) पुणे को भेजे गए नमूनों में स्न्र.7.9, ड्डस्न्रत्न, छ्वह्.1, और ह्क्क1.8.1 वैरिएंट्स की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से लक्षण (खांसी, जुकाम, बुखार) दिखने पर तुरंत टेस्ट कराने और डॉक्टर से परामर्श लेने की अपील की है. हालांकि वर्तमान वैरिएंट्स को घातक नहीं माना जा रहा, लेकिन विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

भारत में कोरोना के मामले 5000 पार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई. देश भर में 5,364 मामले सामने आए हैं।

पिछले 24 घंटों में कोविड से संबंधित चार नई मौतें भी दर्ज की गईं, जिससे इस साल जनवरी से अब तक मरने वालों की संख्या 55 हो गई है।

चिरंजीवी योजना पुन: शुरू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प

जयपुर। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि सिकदर ने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए राहतकारी चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया, जिससे गंभीर बीमारियों

से जूझ रहे मरीजों का इलाज बाधित हो गया है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जब उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर गुस्साए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की।

स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें शांत कराया, जिसके बाद युवक कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर जितेन्द्र सोनी से मिला और ज्ञापन सौंपा।

युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि कुमार सिकदर ने बताया कि जयपुर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सैनी और जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष धर्मवीर पायाला के नेतृत्व में चिरंजीवी योजना को पुन: लागू करने और बीमा राशि को 25 लाख रुपये करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया।

रवि सिकदर ने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए राहतकारी चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज बाधित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने योजना को पुन: शुरू नहीं किया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।

नगर निगम ग्रेटर की सतर्कता कार्रवाई

गोपालपुरा पुलिया के नीचे से हटाया अतिक्रमण, 18 हजार रुपये कैरिंग चार्ज वसूला

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर की सतर्कता शाखा ने आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार शुक्रवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन और गोपालपुरा पुलिया के नीचे से अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। यह

कार्रवाई उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। सतर्कता टीम द्वारा मौके से एक केन्टर सामान जब्त कर निगम के गोदाम में भिजवाया गया, वहीं अतिक्रमण करने वालों से 18 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज भी वसूला गया। अजय कुमार शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाते समय मौके पर मौजूद लोगों को मौखिक रूप से समझाइश दी गई और चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया गया तो भारी जुर्माना एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमित रूप से ऐसे स्थानों पर सतर्कता अभियान जारी रहेंगे।

फर्जी पीएम किसान ऐप से साइबर ठगी का नया जाल

एपीके फाइल डाउनलोड करते ही हैक हो रहा मोबाइल

जयपुर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया साइबर जाल फैलाया जा रहा है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर किसान सम्मान निधि योजना की मोबाइल एप्लीकेशन होने का दावा करने वाला एक फर्जी लिंक या एपीके फाइल शेयर कर लोगों को फांस रहे है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को इस संबंध में सतर्क करते हुए एडवाइजरी संख्या 11/2025 जारी की है।

एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन एवं पीएम किसान योजना की फर्जी एपीके फ़ाइल %व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य माध्यमों से शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए किसान योजना में घर बैठे

रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तुरंत लाभ पा सकते हैं।

एसपी कुमार ने बताया कि लेकिन पुलिस जांच में सामने आया है कि इस फर्जी एपीके फाइल के जरिए बैकडोर मैलवेयर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। इससे मोबाइल का नियंत्रण साइबर अपराधियों के पास चला जाता है। अपराधी फिर मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओटीपी, बैंकिंग एप्स व अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर बैंक खातों से अवैध रूप से धन निकाल रहे हैं।

साइबर क्राइम शाखा ने स्पष्ट किया है कि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन सिर्फ तहसील स्तर के कृषि कार्यालय, केंद्र सरकार के पोर्टल या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से ही किया जाता है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in है। यदि मोबाइल एप डाउनलोड करनी हो तो केवल गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक ऐप ही डाउनलोड करें।

साइबर क्राइम शाखा ने आमजन, विशेषकर किसानों और ई-मित्र संचालकों से अपील की है कि किसी भी फर्जी लिंक या ऐप से सावधान रहें। यदि ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, https://cybercrime.gov.in पोर्टल या निकटतम पुलिस थाना/साइबर थाना पर सूचना दें। पुलिस ने कहा कि समय-समय पर साइबर अपराधी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ऐसे में सजगता व जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।

पौधारोपण से मिलता है महापुण्य-श्रीमती ऋतु शुक्ला

मीनेश चंद्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। पत्र सूचना कार्यालय व केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की अपर महानिदेशक (रीजन) श्रीमती ऋतु शुक्ला ने कहा कि संसार के प्रत्येक मनुष्य को पौधारोपण अवश्य करना चाहिए इससे महापुण्य मिलता है। इस अवसर पर हेल्थ एंड वेलनेस कोच सुश्री सरोज निष्ठा, पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के निदेशक श्री अनुभव बैरवा, पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर उप निदेशक श्री धर्मेश भारती के साथ-साथ केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक संतोष वी. यू ने इस अवसर पर पौधारोपण किया । केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में पौधरोपण कर सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया।

भयावह संघर्ष' को बंद कराए सरकार-गहलोत

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में चल रही उठापटक और विवादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और RCA की एडहॉक कमेटी पर हमला बोला है।

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में चल रही उठापटक और विवादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और RC की एडहॉक कमेटी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर RCA की स्थिति को भयावह बताया और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद RCA में विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में निराशा फैल रही है।

अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे विवादों से क्रिकेटप्रेमियों में बड़ी निराशा का भाव है। ऋष्ट में एडहॉक कमिटी का गठन सरकार ने किया परन्तु लगातार चल रहे विवादों के कारण यहां ढ्ढक्करु तक का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो गया।

उन्होंने कहा कि एडहॉक

कमिटी, क्रीडा परिषद एवं खेल विभाग में विवाद चल रहे हैं और राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। कानूनी तौर पर एडहॉक कमिटी केवल तीन महीने के लिए होती है जिसके दौरान चुनाव करवाने होते हैं परन्तु डेढ़ साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे विवादों से क्रिकेटप्रेमियों में बड़ी निराशा का भाव है। RCA में एडहॉक कमिटी का गठन सरकार ने किया परन्तु लगातार चल रहे विवादों के कारण यहां ढ्ढक्करु तक का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो गया।

बेटे वैभव की गिनाई उपलब्धियां

गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के ऋष्ट अध्यक्ष कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वैभव गहलोत के ऋष्ट अध्यक्ष के कार्यकाल में RCA की चर्चा सकारात्मक कार्यों के लिए हुई। 2019 के बाद ड्ढष्टष्ठ से ऋष्ट पर लगा बैन हटा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय एवं ढ्ढक्करु मैचों का आयोजन शुरू हुआ।

RPL समेत राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ एवं वहां ऋक्करु और ष्टस्रु के मैच का आयोजन हुआ तथा वेदांता समूह के साथ जयपुर के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक बनाने की शुरुआत हुई। इस स्टेडियम का काम भी अब बन्द हो गया है।

राजस्थान के क्रिकेट एवं क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य तथा लाखों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार को हस्तक्षेप कर ऋष्ट में चल रहे भयावह संघर्ष को बन्द करवाना चाहिए जिससे राजस्थान में क्रिकेट का विकास हो सके।

एडहॉक कमेटी में भी तनातनी

RCA की एडहॉक कमेटी में भी आंतरिक विवाद सामने आए हैं। कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर के बीच टकराव की खबरें चर्चा में हैं। बिहाणी ने दावा किया कि राजस्थान के 18 जिला क्रिकेट संघ उनके साथ हैं और उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स एक्ट के तहत एडहॉक कमेटी एक निर्वाचित कमेटी की तरह कार्य कर रही है।

बेंगलुरु में व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे का बेनकाब होना

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा। लेकिन इस जीत के जश्न की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहें का होना और उसे खिलाडियों एवं राजनेताओं द्वारा नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें हो जाने के बावजूद जश्न जारी रहना, दुखद एवं शर्मनाक है।

(लेखक - ललित गर्ग)

बढ़ते तापमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की शानदार जीत के बाद आयोज्य जश्न के मातम, हाहाकार एवं दर्दनाक मंजर ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल ही नहीं खोली बल्कि सत्ता एवं खेल व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है। आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, यह राज्य प्रायोजित एवं प्रोत्साहित हत्या है। पुलिस का बंदोबस्त कहां था? चीख, पुकार और दर्द और क्रिकेट सितारों को देखने की दीवानगी एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक वाकया है जो सुदीर्घ काल तक पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़, निकासी मार्गों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक मामला है, जहाँ भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन एवं सत्ता का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है।

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा। लेकिन इस जीत के जश्न की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहें का होना और उसे खिलाडियों एवं राजनेताओं द्वारा नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें हो जाने के बावजूद जश्न जारी रहना, दुखद एवं शर्मनाक है। प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि खिलाड़ियों को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अवैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है। इस जीत के जश्न में हिस्सा लेने आई भीड़ का एक लाख तक होने का अनुमान था। लेकिन लंबे अंतराल के बाद मिली जीत ने लोगों के उत्साह को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि स्टेडियम के आसपास तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मौत की खबरें मिलने के बावजूद खिलाडियों के साथ जश्न मनाने में जुटा रहना उनकी प्रचार भूख का भौंडा उदाहरण है। जब मौत के बाद वहां पसरा मातम देखकर सब स्तब्ध थे तो सिद्धारमैया क्यों अपने पद की गरिमा एवं जिम्मेदारी को धूमिल कर रहे थे? सोचिए लोगों की मौत के बाद अगर एक मिनट भी जश्न मना, तालियां बजीं, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का मातम में बदलने का नेतृत्व करेगी तो आम लोगों का कांप उठना स्वाभाविक है।

बहरहाल, आईपीएल का आयोजन लगातार नई ऊंचाइयों को छूता हुआ व्यावसायिक क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने में जरूर सफल रहा है। फटाफट क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में भारत के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों विराट कोहली व एमएस धोनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अंततः विराट कोहली का आईपीएल खिताब जीतने का लंबा इंतजार इस जीत के साथ खत्म हुआ। लेकिन धोनी पांच बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग को जीत का खिताब दिलाने से चूक गए। एक तरह से आईपीएल क्रिकेट से कोहली की यह शानदार विदाई साबित हुई। वे इस गरिमामय विदाई के हकदार भी थे। उनके करोड़ों प्रशंसकों की कतारे देख कर राजनेता भी उनकी साथ मंच सांझा करने को उत्सुक दिखे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अन्य मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी भी इसी फिराक में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जश्न मनाते रहे और आमजनता अव्यवस्थाओं के कारण मौत में समाती रही। यह ऐसी दुखद घटना है जो अपनी निर्दयता एवं क्रूरता के लिये लम्बे समय तक कौंधती रहेगी। सिद्धारमैया के इस घटना की तुलना प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रही है।

भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रत्नागढ़ मंदिर में ढाँचागत कमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी। हालही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन एवं प्रयागराज में हुए हादसे में भी अनेकों लोगों की जान गयी। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों में भी भीड़ प्रबंधन की पोल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों है? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बाधाओं को दूर करने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है। रेलवे स्टेशन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त जगह और रास्ते नहीं हैं। कुछ स्थानों पर निकास मार्ग सीमित हैं या अनुपयुक्त हैं, जो भगदड़ का खतरा बढ़ाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों, जैसे कि एआई आधारित निगरानी और ड्रोन कैमरे का उपयोग सीमित है। लोगों को आपातकालीन निकास मार्गों, भीड़ नियंत्रण नियमों, और सुरक्षा उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। गलत सूचना या अचानक दहशत से भीड़ अनियंत्रित हो सकती है और भगदड़ मच सकती है।

भीड़ का व्यवहार कई बार अनियंत्रित हो जाता है, खासकर धार्मिक, खेल एवं सिनेमा आयोजनों में, जहां लोग भावनाओं में बहकर आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। कई बार आयोजनकर्ताओं और पुलिस के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे सुरक्षा चूक हो सकती है। भीड़ प्रबंधन केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों की संरचना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीतियों से गहनता से संबद्ध है। दुर्भाग्यवश, कई बार आयोजकों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते, जिससे जानमाल की हानि होती है। इस परिदृश्य में, बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की मौजूदा स्थिति, उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, हालिया घटनाओं से मिले सबक और प्रभावी समाधानों की चर्चा करना बेहद प्रासंगिक होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में धार्मिक उत्सव, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में लाखों लोग जुटते हैं। ऐसे आयोजनों के लिये पुलिस, होम गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाता है। विश्व के विभिन्न विकसित देशों में भीड़ प्रबंधन के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जापान जैसे देशों में रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ के प्रबंधन के लिये ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट सिस्टम स्थापित किये गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्टेडियमों, एयरपोर्ट्स एवं धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिये एआई आधारित कैमरे, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। हालाँकि भारत में बड़े आयोजनों के लिये प्रशासनिक तैयारियाँ की जाती हैं, फिर भी समय-समय पर कई कमियाँ उजागर होती रही हैं। लेकिन आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम के जश्न के दौरान खामियां ही खामियां देखने को मिली। ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन कोई आसान कार्य नहीं है। लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिये ठोस रणनीति, प्रशासनिक कौशल और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसका इस आयोजन में सर्वथा अभाव रहा। आखिर इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषी लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। प्रेषक:

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

न्याय की साख

किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की साख निर्विवाद रूप से कायम रहनी चाहिए। कामकाज में पारदर्शिता व शुचिता नजर आना संवैधानिक संस्था के लिये अनिवार्य शर्त है। न्यायपालिका की जिन कवायदों को लेकर अंगुलियां उठ सकती हैं, उनको संबोधित करके मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक सराहनीय पहल की है। उनका सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से कोई पद न लेने का संकल्प संस्थागत ईमानदारी व विश्वसनीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा। निस्संदेह, उनके और कई सहयोगियों द्वारा दर्शायी गई यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और इसे स्वतंत्र बनाये रखने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। सीजेआई गवई ने यही साबित करने का प्रयास किया है कि न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद लेना या चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा देना, संवेदनशील नैतिक चिंताएं पैदा करता है। यह भी कि ये प्रवृत्तियां सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करती हैं। निस्संदेह, हितों के टकराव या पक्षपात की कोई भी धारणा केवल विश्वास की कमी को ही बढ़ाती है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इस मुद्दे पर सीजेआई का साहसिक रुख नैतिक नेतृत्व का एक नया मानक स्थापित करेगा- जिसका अक्षरशः और ईमानदारी की भावना से पालन किया जाएगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि न्यायपालिका के भीतर कदाचार के उदाहरण पूरी व्यवस्था के प्रति विश्वास को चोट पहुंचा सकते हैं। इस विश्वास को फिर से बनाने का रास्ता त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है। इसमें दो राय नहीं कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ा कैश-इन-रेजिडेंस का विवाद न्यायपालिका के साथ-साथ कार्यपालिका और विधायिका के लिये कसौटी पर परखने का मामला है। चर्चा है कि आगामी मानसून सत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विवादित पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं कॉलेजियम प्रणाली की बढ़ती आलोचना के बीच सीजेआई गवई का यह कथन कि न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर कोई समाधान नहीं आना चाहिए, सही है। हालांकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, यह एक अनसुलझा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। गाहे-बगाहे अदृश्य न्यायिक भ्रष्टाचार पर भी गंभीर चिंता जतायी जाती रही है। पिछले दिनों पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक करने का कदम सराहनीय था। लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत किया जाना बाकी है। बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के मूल में प्रणालीगत विसंगतियां होने की बात कही जाती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि राजनीतिक नफे-नुकसान के समीकरणों को साधने के लिये सरकारों ने भी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास भी किया है। इसके बावजूद संस्थाओं के भीतर से उभरते शुचिता के संकल्प जन विश्वास को मजबूती देते हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश की साफगोई और विसंगतियों को दूर करने का संकल्प न्यायिक व्यवस्था में जनता के भरोसे को बढ़ाने वाला ही कहा जाएगा। हाल के वर्षों में कुछ शीर्ष न्यायिक संस्थाओं के फैसलों के राजनीतिक निहितार्थ को लेकर सार्वजनिक विमर्श में चर्चाएं होती रही हैं। यही वजह है कि सेवामुक्ति के बाद लाभ के पद स्वीकारने और इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के फैसले को नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता रहा है। निर्विवाद रूप से किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर तथा किसी प्रलोभन को ठुकराकर ही न्याय की साख को बनाया जा सकता है। तभी सही अर्थों में न्यायिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया जा सकता है।

अहिल्याबाई का विरासत पथ बना मोहन का विकास पथ

(लेखक - हर्षवर्धन पान्डे)

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को सुशासन, नारी सशक्तिकरण और जनकल्याण की प्रतीक माना जाता है। अपने शासनकाल में जनकल्याण और समावेशी विकास की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी इस विरासत को न केवल संरक्षित करने का संकल्प लिया है, बल्कि इसे आधार बनाकर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने अपने शासनकाल में सुशासन की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने न केवल प्रशासनिक दक्षता और न्यायप्रियता का परिचय दिया, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। मंदिरों, घाटों, सरायों और जल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक अभ्युदय को बढ़ावा दिया। उनकी यह विरासत आज भी मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का आधार है जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव अपने विजन से नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने और उनके आदर्शों को विकास नीतियों में समाहित करने का संकल्प लिया है। अहिल्याबाई की पुण्य गाथा से आज पूरा प्रदेश सरोबार रहा है जिसके चलते उनके कार्यों की जानकारी आम आदमी तक पहुंच रही है। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने विरासत के साथ विकास के मंत्र को अपनाते हुए मध्यप्रदेश को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी नीतियां और योजनाएं न केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का जो संकल्प लोकमाता लिया था, उसे डॉ. मोहन यादव की सरकार देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से साकार कर रही है। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) मंत्र से प्रेरित है। इस मिशन के तहत बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं जैसे लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना, लखपति दीदी और महिला स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी जैसे कदम उठाए गए हैं।

अहिल्याबाई के शासनकाल में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता का विशेष महत्व था। डॉ. मोहन यादव ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए ई-गवर्नेंस की सुशासन प्रणालियों को प्रदेश में बेहतर ढंग से लागू किया है। उनकी सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जनकल्याण पर्व जैसे अभियान शुरू किए हैं जिनमें शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महारानी अहिल्या के शासनकाल के फैसले, नीतियों से प्रेरित होकर अपनी कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजबाड़ा में रखी जिसमें अहिल्याबाई की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर प्रदेश के विकास के लिए कई निर्णय लिए गए जिसमें 3876 करोड़ रु. की सौगात प्रदेश को दी गई। मोहन सरकार की मौजूदा नीतियों में शामिल सुशासन, जनसुनवाई और महिला सशक्तिकरण उन्हीं से प्रेरित है।डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कई पहल की हैं। अहिल्यादेवी द्वारा निर्मित मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सामुदायिक संरचनाओं के रखरखाव के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय, और सिंहस्थ 2028 जैसे आयोजनों के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। ये प्रयास न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे।

डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस योजना तैयार की है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने बीते डेढ़ वर्ष में औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए उन्होंने न केवल बेहतर नीतियां बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए। इस तरह के भव्य आयोजनों ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं को मजबूती प्रदान की। इसके साथ ही निवेशकों के साथ सीएम डॉ.यादव ने सीधा संवाद स्थापित किया जिससे मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा कर वहां की प्रमुख कंपनियों और निवेशकों से संवाद स्थापित किया। अगले पांच वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।यह योजना उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई है और निवेशकों की बैठकों में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कई घाटों और जलाशयों का निर्माण करवाया था। उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए डॉ. मोहन यादव की सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, और ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। ये परियोजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित होंगी और प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी। इसके अलावा जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मोहन सरकार नई लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। मोहन सरकार फसल का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में'' के सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' चला रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान जन-भागीदारी से चलाया जा रहा है जिसके सकारातमक परिणाम सामने आ रहे हैं जो 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलेगा।

(चिंतन-मनन)

इच्छाएं जीवात्मा को मोह से बांधे रखती हैं

इंद्रियां, मन और बुद्धि काम-वासना के निवास-स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान को ढककर काम-वासना जीवात्मा को मोहित करती है। कामरूपी दुश्मन का नाश करने के लिए यह पता होना ज़रूरी है कि यह रहता कहां है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि काम-वासना किसी एक जगह नहीं रहती, बल्कि यह तो हमारे तीनों शरीरों- स्थूल, सूक्ष्म और कारण में निवास करती है। इसकी पकड़ बड़ी मज़बूत होती है, इसलिए इसका नाश करना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर जब काम-वासना इन्द्रियों में जगती है, तब इन्द्रियां बेकाबू हो जाती हैं। जब यह मन में जगती है तो दूसरे काम करते हुए भी मन में काम-वासना के बारे में ही ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे वक्ति में दिमाग में केवल काम ही भरी रहती है और बुद्धि दूसरा निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए हमारी चेतना की मुख्य जगहों इन्द्रियों, मन और बुद्धि में जैसे ही काम अपना बसेरा डालता है, वहां से ज्ञान गायब हो जाता है। यही वजह है कि बड़े-बड़े ज्ञानियों में भी जब काम उपजता है तो वह उनके ज्ञान को ढक लेता है। काम का मतलब यहां केवल काम-वासना से ही नहीं, बल्कि हमारी अन्य कामनाओं से भी है। कामनाएं या इच्छाएं जीवन भर इंसान का पीछा नहीं छोड़तीं और इस वजह से जीवात्मा का संसार को लेकर मोह बना रहता है।

विचार मंथन

सोवियत रूस की राह चला अमेरिका, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं ट्रंप

(लेखक - सनत जैन)

अमेरिका का आर्थिक संकट दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो चुका है जो अमेरिका की जीडीपी के मुकाबले 122 फ़ीसदी को पार करने जा रहा है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहंकार के चलते सारी दुनिया को जीतने और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए जो टैरिफ बार शुरू किया था उस टैरिफ बार मकड़ जाल में वह स्वयं फंसकर रह गए हैं। कैसे बाहर निकलेंगे उन्हें पता नहीं टेस्ला कंपनी के एलन मस्क ने अरबों रुपए खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने में मदद की थी वही डोनाल्ड ट्रंप अब एलन मस्क से इतने नाराज हैं। उसकी मदद करना तो दूर जो सब्सिडी उसे अभी तक मिल रही थी उसे भी बंद करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई आदमी उनका विरोध करें यह उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अहंकार के मद में चूर हैं। कर्ज पर कर्ज लेते चले जा रहे हैं। सारी दुनिया के देश को धमका रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि अमेरिका के बिना दुनिया का कोई भी काम या दुनिया का कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा लेकिन उसके इस अहंकार पर चीन ने सबसे ज्यादा चोट की है। चीन के सामने अमेरिका घिगयाने के लिए विवश हुआ है। चीन के जवाबी हमले ने ट्रंप के सारे कस और बल को निकाल दिया है। दुनिया में ट्रंप अब कमजोर राष्ट्रपति के रूप में देखे जा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में महंगाई और मंडी बढ़ती चली जा रही है। 2025 की विकास दर 2.0 से घटकर 1.4 फ़ीसदी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में कर्ज और उसके ब्याज का बोझ जिस तरह कैसे बढ़ रहा है। इस पर अंकुश लगाने की स्थान पर जो तुगलकी फरमान डोनाल्ड ट्रंप जारी कर रहे हैं। उसको देखते हुए अब सारे विश्व में यह कहा जाने लगा है। जिस तरह से सोवियत रूस का विघटन 1990 के दशक में हुआ था लगभग वही हालत 2025 में अमेरिका की देखने को मिलने लगी है। जिस तरह से एक-एक करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विशेषज्ञों के साथ अपनी दुनिया बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो गड्ढा वह दूसरों के लिए खोद रहे थे अब उसी गड्ढे में वह स्वयं गिरते चले जा रहे हैं। यह धारणा सारी दुनिया के देशों में बनने लगी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जिस तरह से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाकर चले जाते हैं और अमेरिका उनका कुछ नहीं कर पाता है। अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर जिस तरीके से शेयर बाजार वालस्ट्रीट और अन्य आर्थिक विशेषज्ञ अमेरिका के लिए कर्ज को खतरे की घंटी बता रहे हैं। यदि इस पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी अमेरिका में एक ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है। इसके बारे में अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी अमेरिका एक संघीय देश है। राज्यों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको अनदेखा करते हुए जिस तरह की दादागिरी कर रहे हैं। उसके बाद यह बार-बार कहा जाने लगा है की जो सोवियत रूस का हुआ था यदि वही अमेरिका के साथ हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए 100 वर्ष के इतिहास में अमेरिका सबसे ज्यादा मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में सबसे खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। अमेरिका यदि कमजोर होता है तो वैश्विक स्तर पर अराजकता बढ़ेगी सारी दुनिया में अशांति होगी सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। इस आसन का को लेकर सारी दुनिया के देशों में एक बड़ी चिंता देखी जा रही है। भारत भी इस चिंता से दूर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो तनाव बना है। इसका लाभ चीन और भारत के पड़ोसी देश उठा रहे हैं। चीन उनकी दोनों हाथों से मदद कर रहा है। उन्हें सैन्य हथियारों से लेकर अन्य आर्थिक मदद दी जा रही है। चीन की जो गतिविधियां हैं। वह भारत को कमजोर करने वाली हैं। भारत आज सारी दुनिया के देशों में अलग-अलग पड़ता चला जा रहा है। भारत के लिए भी यह चिंता का सबसे बड़ा विषय है।

कर्ज की इकोनॉमी से जब अमेरिका जैसा देश विघटन के दौर में पहुंच सकता है, तब आसानी से कल्पना की जा सकती है कि भारत के ऊपर जो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। वह भारत को कौन सी दिशा और दशा होगी इसको लेकर भारत की चिंता भी अब देखने को मिलने लगी है।

दो-राष्ट्र सिद्धांत देश के लिए घातक, जब तक ये रहेगा भारत सुरक्षित नहीं

भागवत ने धर्मांतरण को लेकर भी चिंता जाहिर की

नागपुर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन मौके पर देश के सामने खड़ी भीतरी और बाहरी चुनौतियों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने वर्तमान समय में भारत के सामने मौजूद बहुआयामी खतरों का उल्लेख कर कहा कि अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारों, सूचना और आस्था के स्तर पर भी लड़े जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देकर कहा कि भारत के खिलाफ जो शक्तियाँ सक्रिय हैं, वे केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारधारा, सामाजिक विभाजन और भावनात्मक विघटन के ज़रिए देश को कमजोर करने में लगी हैं। भागवत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उदाहरण देकर कहा कि जब देश पर ऐसा कोई हमला होता है, तब पूरा भारत एकजुट होकर उसका जवाब देता है। उन्होंने मोदी सरकार और सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई की सराहना कर कहा कि इससे साफ संदेश गया है कि भारत अब पहले जैसा मूकदर्शक नहीं है।

उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना कर कहा कि यह विचार आज भी देश के कुछ हिस्सों में जीवित है, और जब तक यह सोच बनी रहेगी, तब तक भारत को खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि यह विचार समाज को विभाजित करता है और इसके पीछे कई छुपे एजेंडे हैं, जो भारत की अखंडता के लिए घातक हैं।भागवत ने धर्मांतरण को लेकर भी चिंता जताकर कहा कि लालच, धोखा या दबाव के द्वारा किया गया धर्म परिवर्तन, हिंसा के ही समान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है, तब यह अलग बात है, लेकिन किसी को भ्रमित कर या अपमानित कर धर्म बदलवाना सामाजिक ताना-बाना तोड़ता है। उन्होंने आदिवासी नेता अरविंद नेताम का हवाला देकर कहा कि संघ ही एकमात्र संगठन है जो दशकों से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाता आया है।

उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और रिवाज होने के बावजूद भारतीय समाज एक साझा संस्कृति में बंधा हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

फिल्ममेकर विनोद छाबड़ा का निधन, इंडस्ट्री में छाया शोक

मुंबई।

फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर विनोद छाबड़ा अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका गुरूवार 5 जून को कैंसर की बीमारी से जूझने हुए निधन हो गया। वह 55 साल के थे। बता दें बीते दिनों टीवी एक्टर विभु राघवे का भी कैंसर से निधन हो गया था। अब दिग्गज फिल्ममेकर के निधन से हर कोई बेहद सदमे में हैं और उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है। इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। विनोद छाबड़ा का निधन मुंबई में हुआ। उनके निधन की खबर से फैंस और उनके चाहने वाले दुखी हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। बता दें हाल ही में टीवी एक्टर विभू राघव का भी कैंसर से निधन हुआ था। फिल्ममेकर का अंतिम संस्कार गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में ही उन्हें अखिरी विदाई दी गई। बता दें, विनोद छबड़ा ने न सिर्फ बॉलीवुड में ही नाम कमाया, बल्कि उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु, बंगाली सहित 20 से ज्यादा भाषाओं की फिल्में बनाई हैं। करीब 40 साल से विनोद इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी।

कैप्टन अशोक राव ने संभाली आईएनएस विक्रांत की कमान

नई दिल्ली।

भारतीय नौसेना के कैप्टन अशोक राव ने गुरुवार को देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की कमान संभाल ली। उन्होंने कमोडोर बीरेंद्र एस. बैंस से यह जिम्मेदारी ली है। नौसेना के मुताबिक, अब यह जिम्मेदारी संभालने वाले कैप्टन अशोक राव नौसेना पदक से सम्मानित अधिकारी हैं। नौसेना ने बताया कि कैप्टन राव नौसेना अकादमी के 52वें कोर्स के पूर्व छात्र हैं और उनके पास युद्धपोत संचालन का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने पहले आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस कोरा और आईएनएस निशंक जैसे प्रमुख युद्धपोतों की भी कमान संभाली है। इसके अलावा, वह कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग में रक्षा सलाहकार के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। आईएनएस विक्रांत की कमान संभालना कैप्टन राव के लिए एक प्रतिष्ठित उपलब्धि है, जो भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत की यह नई नेतृत्व पारी भारतीय समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

बकरीद पर विट्ठल....90 हजार में, 'शेरा' व 'बिल्ला' 35 हजार में बिके

प्रयागराज। देश में बकरीद सात जून को है। इस लेकर बकरा बाजार में रौनक बढ़ गई है। बीते साल की अपेक्षा इस बार बकरों की कीमत बढ़ी हुई है। करेली स्थित बकरामंडी में 90 हजार में विट्ठल, 35 हजार रुपये में 'शेरा' व 'बिल्ला' बिका। विट्ठल को बेचने वाले दरियाबाद निवासी मो. जमाल ने बताया कि तीन वर्ष से बकरे को तैयार कर रहे थे। अकबरपुर निवासी एक शख्स ने विट्ठल को खरीदा है। हटिया स्थित बकरा मंडी के साथ ही दरियाबाद, करेली के रसूलपुर, असकरी मार्केट, नूरुल्ला रोड, नखासकोहना, अटाला, जीटीबी नगर में खरीददारों की भीड़ जुट रही है। कई खूबियों वाले कुर्बानी के जानवर यहां दिख रहे हैं। बकरे का कारोबार करने वालों ने बताया कि बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार बकरों की कीमत बढ़ी हैदेसी नस्ल के बकरों की कीमत 10 से 20 हजार रुपये के बीच है। यह बकरे गंगापार व यमुनापार से लाए गए हैं। वहीं, मप्र के बाकी, सियावल, दुदनिया, इमिलिया के साथ ही कौशांबी के चायल व पिपरी से बकरे लाए जाने वाले बकरे 15-25 हजार रुपये के बीच हैं। राजस्थानी बकरों की नस्लों में अलवरी, सिरोही, शेखावाटी, लोही, परबतसरी आदि भी बकरामंडी में हैं। राजस्थान से लाए गए 'शेरा' व 'बिल्ला' 35 हजार रुपये में बिके। बकरीद को लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है। बच्चों को नए कपड़े दिलाने के साथ लोग टोपी, इत्र आदि की खरीददारी कर रहे है। महिलाएं भी पर्व के लिए घरेलू उपयोग की सामग्री की खरीददारी करने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। शापिंग माल्स, चौक, सिविल लाइंस, कटरा, सुलेमसराय, कोठापार्चा आदि बाजार में दुकानों पर खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है।

बीते 20 वर्षों से भूभुजोत टनल के निर्माण की उम्मीद में बैठे लोगों को अब गडकरी से आस

टनल बनने से मंडी और कुल्लू जिले आपस में जुड़ जाएंगे

मंडी।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी के लोग बीते 20 वर्षों से भूभुजोत टनल के निर्माण की आस लगाए बैठे है। यहां चौहारघाटी से कुल्लू जिले की लगवैली तक एक टनल के निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन यह अभी तक धरातल पर नहीं आया है। इस टनल के बनने से मंडी और कुल्लू जिले आपस में जुड़ जाएंगे। चौहारघाटी और लगवैली के लोगों को अभी आपस में मिलने के लिए या भूभुजोत को पैदल पार करना पड़ता है या सड़क मार्ग से 100 किमी से अधिक का सफर करना होता है। टनल के बनने से यह दूरी मात्र चंद मिनटों में पूरी होगी। यही नहीं, इस टनल का निर्माण सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। सेना की तरफ से ही इसके निर्माण का सुझाव भी दिया गया है. ग्राम पंचायत बरोट के प्रधान ने बताया कि अभी सेना का सारा काफिला पालमपुर से मंडी और फिर कुल्लू होकर लेह की तरफ जाता है। यदि टनल बनाती हैं तब सेना को कुल्लू पहुंचने में आसानी होगी और उनका 50 किमी से अधिक का सफर बचेगा। भूभुजोत टनल के निर्माण का दूसरा पहलू यह भी है कि इससे दुर्गम चौहारघाटी के पर्यटन कारोबार को नए पंख लग जाएंगे। जब लोग यहां से होकर कुल्लू-मनाली की तरफ जाएंगे, तब चौहारघाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए स्वत: ही रुक जाएंगे। चौहारघाटी में अभी लोग बरोट जाना ही पसंद करते हैं, जबकि इसके अलावा पूरी घाटी में प्राकृतिक सौंदर्य का अपार भंडार मौजूद है। इसकारण स्थानीय लोग केंद्र और प्रदेश सरकार से टनल के निर्माण की बार-बार मांग कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लोगों को टनल निर्माण के लिए आश्वस्त किया है। लेकिन अब लोगों को इंतजार इस कार्य के धरातल पर शुरू होने का है। लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार कार्य को जल्द से जल्द करवाकर क्षेत्र के लोगों को इसकी सौगात देगी।

पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट से तीन गुना ज्यादा नुकसान उठा चुके मस्क

ट्रंप से तनाव के कारण 152 बिलियन डॉलर का भारी भरकम नुकसान

नई दिल्ली।

दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टकराना महंगा पड़ गया है। बजट बिल को लेकर ट्रंप और मस्क में ठन गई है। इसका असर टेस्ला के शेयरों पर भी दिख रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भारी गिरावट आई। कंपनी का शेयर 14 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट से कंपनी को सिर्फ तीन घंटे में 152 बिलियन डॉलर का भारी भरकम नुकसान हुआ। यह टेस्ला के इतिहास का सबसे बुरा दिन था।

टेस्ला के शेयरों में गिरावट से मस्क की नेटवर्थ में भी भारी कमी आई। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ में 33.9 अरब डॉलर की गिरावट आई। जो पाकिस्तान के कुल डिफेंस बजट से तीन गुना है। बीते साल यानी 2024 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 11 अरब डॉलर था। गिरावट से मस्क की नेटवर्थ अब 335 अरब डॉलर रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 97.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है। यह रकम गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ (82.5 अरब डॉलर) से ज्यादा है।

ट्रंप और मस्क में तकरार से निवेशक बुरी तरह डरे हैं। पहले निवेशकों को उम्मीद थी कि मस्क की कंपनियों को ट्रंप प्रशासन से अच्छे संबंध होने का फायदा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यह विवाद सरकार के बजट बिल को लेकर शुरू हुआ। कभी ट्रंप के लाड़ले रहे मस्क ने बजट बिल को घिनौना बताया था। इसके जवाब में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया! ट्रंप की धमकी का टेस्ला के शेयरों पर बहुत बुरा असर पड़ा।

कंपनी का वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे गिर गया और गुरुवार को 916 बिलियन डॉलर पर आ गया। टेस्ला के साथ-साथ स्पेस एक्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। मस्क की रॉकेट कंपनी को संघीय सरकार से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसमें नासा के भी कई अहम मिशन शामिल हैं।

गुरुग्राम में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन शुरु, 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज

लगातार अवैध कॉलोनियों पर चल रहा बुलडोजर

गुरुग्राम।

गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम पुलिस से जमीन मालिकों और भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। डीटीपीई कार्यालय की ओर से मई में भोंडसी, बहरामपुर, कादरपुर, महेंद्रवाड़ा, बिधवाका, सोहना के गांव खेड़ला में अवैध रूप से पनप रही 13 कॉलोनियों को तोड़ दिया गया था। ये कॉलोनियां करीब 39 एकड़ जमीन पर बन रही थीं। जांच के दौरान डीटीपीई कार्यालय ने इन जमीनों के मालिकों और भूमाफियाओं के नाम पर जुटाए। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। बता दें कि, अप्रैल में 10 कॉलोनियों को तोड़ा गया था। इन्हें काटने के आरोप में करीब 50 जमीन मालिक और भूमाफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है।

इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर रोक लग गई है। डीटीपीई कार्यालय ने तहसीलदार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया हैं कि इन कॉलोनियों की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में लाल एंट्री में डाला जाए। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने लोगों से अपील है कि वे अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियां में प्लॉट नहीं खरीदें। इनके ऊपर निर्मित मकान कभी भी टूट सकते है। उनकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो सकती है। भूमाफियाओं के बहकावे में नहीं आएं। प्लॉट खरीदने से पहले डीटीपीई कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में कतई न आएं। ठग तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं।

रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भूमाफिया करार या जीपीए के माध्यम से प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डीटीपीई ने कनिष्ठ अभियंता को आदेश जारी किए हैं कि वे इसके ऊपर नजर बनाकर रखें। यदि कोई सूचना मिलती है, तब कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। किसी भी कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाए। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुवार को गांव साढराणा में अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया।

8 जून को रिलीज होगी एटनबरो की डॉक्यूमेंट्री ओशियन विद डेविड एटनबरो

डॉक्यूमेंट्री में समुद्रों की खूबसूरती, रहस्यों और खतरों की झलक देखने को मिलेगी

मुंबई।

जीव विज्ञानी, इतिहासकार और लेखक डेविड एटनबरो अपनी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री ओशियन विद डेविड एटनबरो के साथ दर्शकों को समुद्री सफर पर जाने को लिए हैं। डॉक्यूमेंट्री की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। उन्होंने बताया कि डेविड एटनबरो की नई डॉक्यूमेंट्री ओशियन विद डेविड एटनबरो विश्व महासागर दिवस पर यानी 8 जून को रिलीज होगी। यह डॉक्यूमेंट्री समुद्रों की खूबसूरती, उनके रहस्यों और खतरों की झलक दिखाएगी और खास अंदाज में रोचक कहानी पेश करेगी।ओशियन विद डेविड एटनबरो में समुद्री जीवन, नई प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की खोज के साथ मछली पकड़ने की हानिकारक तकनीकों जैसे ड्रेजिंग और बॉटम ट्रॉलिंग के पर्यावरण पर बुरे प्रभावों को भी दिखाया है। मनोरंजन और रोमांच के साथ कहानी को गंभीर मोड़ दिया गया है। ओशियन विद डेविड एटनबरो समुद्री विज्ञान पर आधारित है और इसे नेशनल जियोग्राफिक प्रिस्टीन सीज के संस्थापक एनरिक साला समेत वैज्ञानिक सलाहकारों की टीम द्वारा समर्थित है। एटनबरो कहते हैं कि समुद्रों की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन इसे ठीक करने के तरीके भी हैं। इसमें वैज्ञानिकों की सलाह और नेशनल जियोग्राफिक की मदद से समुद्रों को बचाने का संदेश दिया गया है। एटनबरो ने बताया कि मेरा जीवन महासागर की खोज पर ही आधारित है। पिछले 100 सालों में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने नई प्रजातियों, जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों का पता लगाया है, जो एक युवा के रूप में मेरी कल्पना से परे है। इस फिल्म में हम उन अद्भुत खोजों के बारे में बता रहे हैं, कि हमारे महासागर की स्थिति इतनी खराब क्यों है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत करने के लिए सर डेविड से बेहतर कोई नहीं है और मुझे खुशी है कि वह नेशनल ज्योग्राफिक के साथ पहली बार ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जो प्रासंगिक है और उनके दिल के करीब है। यह डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफिक और जियोहॉटस्टार पर 8 जून को दिखाई जाएगी।

पहाड़ों में छिपा वो रहस्य क्यों अटकने लगती हैं सांसें चारधाम यात्रा के दौरान हुईं कई मौतें

नई दिल्ली।

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चालू है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चारो धामों में पहुंच रहे हैं।

इस बीच श्रद्धालुओं की मौत की खबरें भी आ रही है। ऐसे में आइए जानते है कि पहाड़ों पर क्यों लोगों की सांसें थमने लगती है। इसका क्या कराण है। साथ ही जानते हैं कि पहाड़ों पर यात्रा से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड के चार धाम केदारानाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है। हर साल बड़ी तादाद में श्रद्धलु इस चारधाम की यात्रा पर जाते हैं। इस बार भी ये यात्रा शुरू है। हालांकि चारधाम यात्रा के दौरान अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आइए जानते है कि पहाड़ों पर ऐसा क्या है, जिसकी वजह से लोगों की सांसें थम जा रही हैं। साथ ही जानते हैं कि पहाड़ों पर यात्रा के समय किन बातों का खयाल रखना चाहिए। चारधाम यात्रा हर साल मई में शुरू होती है।

हिंदुओं के लिए ये यात्रा बहुत पावन मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर जाते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है पहाड़ों पर लोगों की सासें क्यों थम रही हैं। दरअसल, चारधाम के मंदिरों की ऊंचाई समुद्र तल से तीन हजार फिट है। आप जितना ऊंचाई पर पहाड़ पर जाते हैं, हवा में ऑक्सिजन लेवल उतना कम हो जाता है। समुद्र तल में हवा में ऑक्सिजन की मात्रा 21 फीसदी बताई जाती है, लेकिन तीन हजार फीट की ऊंचाई पर जाने में हवा में ऑक्सिजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इसे डॉक्टर्स और मेडिकल की भाषा में 'हाइपोक्सिया' कहा जाता है। जो लोग मैदानी क्षेत्रों से सीधे पहाड़ पर चले जाते हैं, ये हालात उन लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। डॉक्टर्स बिना किसी तैयारी के ऊंचाई पर चढ़ने से 'एक्यूट माउंटेन सिकनेस' का खतरा बढ़ने की बात कहते हैं। सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना और सांस फूलना इसके लक्षण हैं। कई लोग बिना मेडिकल जांच और तैयारी के पहाड़ की ओर से चल पड़ते हैं, जिससे खतरा और बढ़ता है। पहाड़ों पर जान का जोखिम सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है, जो दिल के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस के बिमारियों के मरीज होते हैं।

पाकिस्तान पर बरसे मोदी, 'ऑपरेशन सिंदूर'.....उनकी शर्मनाक शिकस्त का प्रतीक

22 अप्रैल को इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया गया

कटरा।

शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के एक दिवसीय दौरे पर कटरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित कर पाकिस्तान को खूब खरीखोटी सुनाई। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर कहा कि 22 अप्रैल को इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया गया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश का मकसद भारत में दंगे कराना था और इसकारण पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पीएम मोदी ने कहा, ÷पाकिस्तान ने पहलगाम में इन्सानियत और कश्मीरियत, दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था, कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था, इसकारण पाकिस्तान ने टूरिस्टों पर हमला किया। उन्होंने कहा, ÷जम्मू-कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वहीं आतंकवाद है, जिसने घाटी में स्कूल जलाए, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र कर कहा, ÷आज 6 जून हैज संयोग से ठीक एक माह पहले, आज की ही रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम सुनेगा, तब अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह वार करेगा। वर्षों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थीं, वे कुछ ही मिनटों में खंडहर बन गईं।

प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी ने कहा, ÷ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमारी सरकार ने ही पूरा करके दिखाया। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थरज ये प्रोजेक्ट पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, वह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच पहली ट्रेन सेवा है।

जिस सेना ने पूरे परिवार को तबाह किया उसी का समर्थन कर रहे बिलावल

पाकिस्तान की राजनीति भारत-विरोधी रही है

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर भारतीय सियासी गलियारों में चर्चा में हैं।

इस बार उन पर भारत के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने निशाना साधा है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के प्रति बिलावल के रुख पर सवाल उठाए हैं। देवड़ा ने कहा कि 'ये कितना हैरान करने वाला है कि बिलावल भुट्टो आज उसी पाकिस्तानी सेना का समर्थन कर रहे हैं, जिसने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उनके दादा जुल्फिकार अली भुट्टो को सेना ने फांसी दी, उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या सेना समर्थित आतंकवादियों ने की और उनके दो मामाओं की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हुई, जिसके पीछे भी सेना-आतंकवादी गठजोड़ को ही जिम्मेदार माना जाता है। फिर भी बिलावल उन्हीं का साथ दे रहे हैं।

देवड़ा का यह बयान सीधे पाकिस्तान की सत्ता संरचना पर सवाल खड़ा करता है, वह भी जब पाकिस्तान में सेना का दखल सियासत से लेकर मीडिया तक हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलावल जो खुद एक नेता हैं, कई बार सेना के खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन हाल के महीनों में उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। वे अब पाक सेना के साथ राजनीतिक तालमेल की कोशिश करते दिख रहे हैं। देवड़ा का तंज इसी पृष्ठभूमि में आया है।भारत में यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका हमेशा भारत-विरोधी नीतियों से जुड़ी है। देवड़ा ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे 'स्मृति और नैतिकता की हार' बताया है।

पहला कॉलम

पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर लहराया तिरंगा, देश को दी बड़ी सौगात

जम्मू।

जम्मू कश्मीर में केंद्र की मोदी सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवागमन के बेहतर साधन जुटाने में लगी हुई है। ऐसे ही प्रयासों के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की ऐतिहासिक सौगात दी है। इससे पहले उन्होंने ब्रिज पर पहुंचकर भारत का गौरव तिरंगा लहराया और ब्रिज को काफी देर तक निहारा। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लिंक से जुड़ गया है। कई साल पहले घाटी को देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा गया था। अब जाकर वह साकार हुआ है। इससे कश्मीर वैली में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यवसाय-कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है।

चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। यह भूकंप के लिहाज से जोन-5 में स्थित है। यह ब्रिज दो पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैष्णव ने बताया कि इस ब्रिज के निर्माण में नींव और मेन स्ट्रक्चर को जोड़ने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन चुनौतियों को पार किया गया, जिससे यह परियोजना न केवल तकनीकी, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अनूठा है। चिनाब और अंजी ब्रिज के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों की तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेशन का प्रदर्शन हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेलवे

लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना सपना था, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और अथक प्रयासों से साकार हो रहा है।

भारत में जल्द मिलेगी स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस

इलॉन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी

नई दिल्ली।

इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। अब उसे सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अप्रूवल का इंतजार है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले भारती के वनवेब और रिलायंस जियो को देश के भीतर अपनी सर्विस देने के लिए मंजूरी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में महीनेभर अनलिमिटेड डेटा देगा।

स्टारलिंक के प्रमोशनल प्लान में अनलिमिटेड डेटा

स्पेसएक्स भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज मंथली 10 डॉलर यानी लगभग 840 रुपए से कम कीमत वाले शुरुआती प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान से शुरू करेगा। स्टारलिंक समेत सैटेलाइट कम्यूनिकेशंस कंपनियों का टारगेट अपने यूजर बेस को तेजी से बढ़ाना है। यह मिड-टू-लॉन्ग टर्म में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कस्टमर तक पहुंच सकता है। इससे कंपनियों को भारी स्पेक्ट्रम कॉस्ट की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

सस्पेंड एएसपी के घर हथियार बरामद

समस्तीपुर(ईएमएस)। समस्तीपुर में सस्पेंड एएसपी सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला है। शुक्रवार को एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम सरोज सिंह के घर रेड करने पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही सरोज की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फिर एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। छापेमारी के दौरान घर से करीब 500 राउंड जिंदा कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं। मामला मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा दियारा का है। पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

सस्पेंड एएसपी के घर हथियार बरामद

समस्तीपुर।

समस्तीपुर में सस्पेंड एएसपी सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला है। शुक्रवार को एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम सरोज सिंह के घर रेड करने पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही सरोज की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फिर एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। छापेमारी के दौरान घर से करीब 500 राउंड जिंदा कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं। मामला मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा दियारा का है। पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बलात्कारी एनकाउंटर में ढेर

लखनऊ।

लखनऊ में ढाई साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। शुक्रवार तड़के देवी खेड़ा इलाके में गन्ना संस्थान के पास पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा (24) को घेर लिया। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में 2 गोली लगी। आलमबाग थाना पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 5 जून की रात आरोपी आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे मां-बाप के साथ सो रही बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गया था। रात करीब ढाई बजे मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के पास ले जाकर मासूम के साथ दरिंदगी की। बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर वहां छोड़कर भाग गया।

राम मंदिर निर्माण में अब तक लग चुका है 50 करोड़ का सोना

अयोध्या।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण में 45 किलोग्राम खरा सोने का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि मंदिर में कुल 45 किलोग्राम खरा (24 कैरेट) सोने का इस्तेमाल किया गया है। बृहस्पतिवार को राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम, देवी सीता और भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा राम भक्त हनुमान से सजे राम दरबार की पूरे विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मिश्रा ने बताया कि मंदिर में इस्तेमाल किये गए सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है। मंदिर के भूतल पर बने दरवाजों और भगवान राम के सिंहासन में बड़े पैमाने पर सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, शेषावतार मंदिर में सोने का काम अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन संग्रहालय, सभागार और अतिथि गृह समेत मंदिर परिसर के अन्य हिस्से अभी निर्माणाधीन हैं। इनका काम दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। मिश्रा ने कहा कि गुरुवार को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, अब वहां लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल, केवल सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को राम दरबार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं को पास लेने होंगे जो निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि बृहस्पतिवार को मंदिर में सात विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सम्पन्न हुआ। उन्होंने

कहा कि गर्भगृह के ऊपर स्थित पहली मंजिल पर स्थापित मूर्तियों में बीच में राम दरबार, उत्तर-पूर्वी कोने में शिवलिंग, दक्षिण-पूर्वी कोने में गणपति, दक्षिणी भाग के मध्य में हनुमान, दक्षिण पश्चिमी कोने में सूर्य, उत्तर-पश्चिमी कोने में भगवती और उत्तरी भाग के मध्य में अन्नपूर्णा माता शामिल हैं। राय ने कहा कि भीषण गर्मी और धूप से बचने के लिए की गई सीमित व्यवस्थाओं के कारण कई श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राणा की अगली कोर्ट पेशी 9 जुलाई को होगी। इसका अर्थ है कि राणा को अब 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से आंतकी राणा को वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान राणा ने अपने परिवार से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। बताया गया हैं

कि मास्टरमाइंड राणा ने परिवार से बातचीत के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। राणा की अर्जी पर कोर्ट 9 जून को सुनवाई करेगा। जब राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया गया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। राणा के वकील ने तर्क दिया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है।

इसके पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज किया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था।

प्रियांक खड़गे का बयान, हमारी सरकार किसी को भी बलि का बकरा नहीं बना रही

बेंगलुरु।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर टिप्पणी कर कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। खड़गे ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हमारी सरकार ने किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया है। भाजपा की आलोचना का जवाब देकर खड़गे ने पलटवार कर कहा कि भाजपा चाहती है कि सीएम, डीसीएम और गृह मंत्री इस्तीफा दें, इसके हिसाब से, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे, पहलगाम हमले के लिए अमित शाह इस्तीफा दे, विदेश नीति की विफलता के लिए एस जयशंकर को इस्तीफा और पूरे देश को गुमराह करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या कुंभ मेले में भगदड़ नहीं मची? हमें यह भी नहीं पता कि कितने लोग मारे गए। हम कम से कम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और जिम्मेदारी ले रहे हैं... हम हताहतों की संख्या नहीं छिपा रहे हैं। उन्होंने माना कि राज्य सरकार बेहतर योजना बना सकती थी, हां, हम बेहतर योजना बना सकते थे और चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते थे, और हम इस पर विचार कर रहे हैं...।

मणिपुर में आठ उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद

इंफाल। मणिपुर के इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों से सुरक्षा बलों ने विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि घारी माखा लेईकोई क्षेत्र से प्रतिबंधित 'यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलीपाक' (यूपीपीके) के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चार सदस्यों को ताओथोंग खुनौ और बिष्णुपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिष्णुपुर के वांगू अहलुप मयई लीकाई में पीआरईपीएके (प्रो) के एक सक्रिय सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ उग्रवादियों के पास से पिस्तौल सहित हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किया गया। राज्य में जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में हाईवे किनारे ट्रामा सेंटर बनने की मांग पकड़ रही जोर

देहरादून। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसके बाद मोदी सरकार ने सभी राज्यों से अपने यहां हाईवे पर हर 100 मीटर पर ट्रामा सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड में ट्रामा सेंटर बने, लेकिन जिला चिकित्सालयों में तैयार हुए है। इसमें से अधिकांश हाईवे से दूर हैं। यह देखकर राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर हाईवे किनारे ट्रामा सेंटर बनने को कहा है।सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय से मदद मिलने पर उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है और वह है स्वर्णिम समय यानी गोल्डन आवर। विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को यदि दुर्घटना के पहले घंटे में इलाज मिल जाए, तब उसकी जान बचने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है।

अरवल शहर में ग्रीनफील्ड बायपास बनाने की स्वीकृति

अरवल। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अरवल शहर में 12.8 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बायपास बनाने की स्वीकृति मिली है। बायपास निर्माण में छह अरब से ज्यादा रुपए खर्च होने है। शहर के बाहर बायपास बनाने की मांग स्थानीय लोग कई वर्षों से कर रहे थे। लोगों की मांग पर राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। पटना-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर वाहनों के भारी दबाव के कारण शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनाती है। इससे निपटने के लिए पथ निर्माण विभाग ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बायपास निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था। शहर के भगत सिंह चौक के समीप तीन मोहानी मोड़ रहने के कारण प्रत्येक दिन रुक-रुक कर सड़क जाम की समस्या होती है।

20 दिन में 93 से 5364 हुए कोरोना केस, 55 मौतें

24 घंटे में 500 नए मामले; ओडिशा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य

-नई दिल्ली/मुंबई।

देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देशभर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वैरिएंट्स से जनवरी से अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 53 की मौत 15 दिनों में हुई हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से दो और मौतें दर्ज की गईं। इनमें एक पांच महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं,

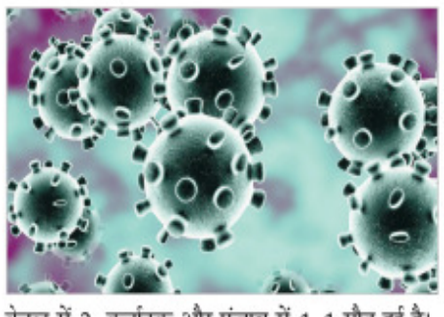

केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में 1-1 मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई है। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कोविड गाइडलाइन के तहत खोले गए हैं। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि जिन बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे हल्के लक्षण हैं, उन्हें स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य है। गंभीर लक्षण वाले बच्चों को घर पर ही रहकर आइसोलेट होने की सलाह दी गई है।

बेंगलुरु भगदड़...अब सरकार एक्शन में

सीएम सिद्धारमैया ने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को हटाया

-सूचना विभाग के प्रमुख का ट्रांसफर; आरसीबी मार्केटिंग हेड, इवेंट कंपनी के 3 अधिकारी हिरासत में

बेंगलुरु।

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को एक और बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के. गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। वहीं सूचना विभाग के प्रमुख हेमंत निंबालकर का ट्रांसफर कर दिया गया है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। इधर, बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में था।

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। इन अधिकारियों की पहचान किरण, सुमंथ और सुनील मैथ्यू के रूप में हुई है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के दो अधिकारी- सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं।

केएससीए के अफसरों की गिरफ्तारी पर रोक

दूसरी तरफ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) को 16 जून तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। केएससीए ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी।

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को केएससीए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित। (इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717